अति तत्काल

फाइल संख्या आर-11016/2/2015-पी0 एण्ड सी0
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 15 मई, 2020

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए अप्रैल, 2020 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **अप्रैल, 2020** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

जसबीर तिवारी

(जसबीर तिवारी)
अवर सचिव (पी एंड सी)
दूरभाष नं0 2338 2525

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के निजी सचिव
2. माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री के निजी सचिव
3. मंत्रिपरिषद के अन्य सभी सदस्य
4. डॉ पी. के. मिश्रा, माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
5. पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. उपराष्ट्रपति के सचिव
7. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
8. भारत सरकार के सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)
9. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली
10. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
11. तकनीकी निदेशक (एन.आई.सी.), को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

*****

अप्रैल, 2020 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलाप है।

1. <u>प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)</u>

पीएमजीकेएवाई पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ, 3 माह के लिए (अप्रैल से जून, 2020 तक) एनएफएसए लाभार्थियों को प्रति परिवार 1 किलोग्राम दाल का भी प्रावधान शामिल है। इस कार्यकलाप में तूर और मसूर जैसी दालों की प्रोसेसिंग तथा राज्यों को उनका वितरण शामिल है। प्रारंभ में, मिलों को खोलने, श्रमिकों की उपलब्धता तथा ट्रकों की आवाजाही में कठिनाइयां हो रही थी, जिसके कारण वितरण मे देरी हुई। फिर भी, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अप्रैल माह में 1.96 लाख मीट्रिक टन दालों के मासिक आबंटन में से 1.76 लाख मीट्रिक टन का वितरण हुआ जिसमें से उनके द्वारा 1.03 लाख मीट्रिक टन की प्राप्ति हुई है और अंतिम लाभार्थियों को 0.28 लाख मीट्रिक टन दालें वितरित हुई।

2. <u>दालों और प्याज का बफर स्टॉक</u>

इस माह के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा करने के लिए आईएमसी की बैठकों का आयोजन किया गया। 50,000 मीट्रिक टन के बफर के सृजन के लक्ष्य के साथ मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के तहत नेफेड ने प्याज की खरीद को आरंभ कर दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पीएसएफ के तहत 3.5 लाख मीट्रिक टन तूर के अतिरिक्त खरीद को मंजूरी दी गई जिससे पीएसएफ के तहत एमएसपी पर तूर के खरीद 5.5 लाख मीट्रिक टन पहुंच गई। इस संबंध मे नेफेड को 1,160 करोड़ रू. का अग्रिम भुगतान भी जारी किया जा चुका है। नेफेड ने यह सूचित किया है कि अप्रैल, 2020 के अंत तक लगभग 1.21 लाख मीट्रिक टन की अधिप्राप्ति हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, नामित एजेंसियों को पीएसएफ के तहत 1.5 लाख मीट्रिक टन मसूर दाल की अधिप्राप्ति के संबंध में अनुमोदन की सूचना दे दी गई है।

3. <u>विधिक मापविज्ञान अधिनियम</u>

पूर्व-पैकबंद वस्तुओं के विनिर्माताओं या पैककर्ता या आयातकों को जीएसटी के कारण बढ़ी हुई कर राशि के समावेशन के बाद जीएसटी के संशोधन से पूर्व विनिर्मित /पैकबंद/आयातित अनबिके स्टॉक, यदि कोई हो, पर 30 सितंबर 2020 तक मौजूदा खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) के अतिरिक्त संशोधित खुदरा मूल्य (एमआरपी) घोषित करने की मंजूरी दी गई। विनिर्माताओं/पैककर्ताओं को पूर्व-मुद्रित विनिर्माण तिथि के साथ मौजूदा पैकेजिंग सामग्री/रेपरों का प्रयोग करने की मंजूरी दी है क्योंकि कोविड-19 मौजूदा स्थिति के कारण लगाए गए नियमों के तहत 30 सितंबर, 2020 तक निर्धारित समय-सीमा के भीतर इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।

4. मुद्रास्फिति की वार्षिक दर का ब्यौरा इस प्रकार हैं-

क्रम सं.	**सूचकांक**	**मुद्रास्फिति दर (%) में**		
		मार्च 2020 (अंतिम)	**फरवरी 2020 (अंतिम)**	**मार्च 2019 (अंतिम)**
1.	थोक मूल्य सूचकांक # (वार्षिक)	1.00	2.26	3.10

2.	थोक मूल्य सूचकांक # (खाद्य सामग्री)	4.91	7.79	5.24
3.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार)	5.50	6.84	7.67
4.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (मिश्रित)*	5.91	6.58	2.86
5.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)*	8.76	10.81	0.30

- **श्रृंखला 2012=100 # नया आधार वर्ष 2011-12=100**

अनुलग्नक -I

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य – पिछले माह की तुलना में रूझान

राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा संसूचित, पूरे देश के 114 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक खुदरा मूल्य मार्च, 2020 की तुलना में अप्रैल, 2020 माह के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और नीचे दिया गया है -

आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतें (रुपये/कि.ग्रा.)

क्रम संख्या	वस्तु	अप्रैल, 2020 (अद्यतन)	मार्च, 2020 (विगत माह)	अंतर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	34	33	1
2	गेहूं	29	29	0
3	आटा	31	30	1
4	चना दाल	69	65	4
5	तूर दाल	95	87	8
6	उड़द दाल	104	97	7
7	मूंग दाल	109	99	10
8	मसूर दाल	73	67	6
9	चीनी	40	39	1
10	दूध (प्रति लीटर)	46	46	0
11	मूंगफली का तेल	144	138	6
12	सरसों का तेल	118	117	1
13	वनस्पति	90	88	2
14	सोया तेल	101	98	3
15	सूरजमुखी का तेल	110	106	4
16	पाम ऑयल	89	87	2
17	गुड़	47	46	1
18	खुली चाय	219	217	2
19	पैकबंद नमक	16	16	0
20	आलू	26	23	3
21	प्याज़	28	31	-3
22	टमाटर	22	21	1

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

अनुलग्नक-II

उपभोक्ता मामले विभाग

1. दीर्घकालीन अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के कारण लंबित हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले:

शून्य

2. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन:- **ई-समीक्षा पोर्टल पर अद्यतन कर दिया गया है।**

3. तीन माह से अधिक समय से लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृति' मामलों की संख्या:

शून्य

4. ऐसे मामलों का विवरण जिनमें सरकार के कार्य व्यापार नियमों अथवा स्थापित नीति से विपथन हुआ है:

शून्य

5. **ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति**

फाइलों की कुल संख्या	ई-फाइलों की कुल संख्या
112	**101**

6. **लोक शिकायतों की स्थिति** :

अप्रैल, 2020 माह में निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	**अप्रैल, 2020** माह के अन्त में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या
766	**317**

7 **राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत शिकायतों की स्थिति**

अप्रैल, 2020 माह के दौरान, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत डॉकेटों की कुल संख्या	**अप्रैल, 2020** माह के अंत तक निपटाए गए कुल डॉकेटों की संख्या
23512	**16874**

8. **न्यूनतम शासन, अधिकतम अभिशासन**:

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष पूरे देश के 114 केन्द्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। ये कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यत: ऑनलाइन तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को विभाग की वेबसाइट द्वारा तत्काल प्रसारित किया जाता है। कीमतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। अनुदेशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार नेमी प्रकार के अन्य सरकारी कार्य भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं ताकि विलंब से बचा जा सके तथा अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

*****